



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 10 राँची, बुधवार 4 चैत्र 1937 (श०)

25 मार्च, 2015 (ई०)

विषय-सूची

| पृष्ठ | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 152-157 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। | भाग-4—झारखण्ड अधिनियम |
| भाग 1—क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश । | भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । |
| भाग 1—ख—मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि। | भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । |
| भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि। | भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। |
| भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा | भाग-9- विज्ञापन --- निकले |
| भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि । | भाग-9-क—बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं |
| भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण। | भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि। |
| | पूरक-- ... |
| | पूरक अ ... |

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

02 फरवरी, 2015

संख्या-4/नि0सं0-12-112/2014 का. 2011 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री अनिल कुमार सिंह, झा0प्र0से0, सम्प्रति अंचल अधिकारी, देवरी, गिरिडीह को (क) दिनांक 05 जून, 2014 से 25 अगस्त, 2014 तक उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत एवं (ख) दिनांक 26 अगस्त, 2014 से 30 अगस्त, 2014 तक अदेय अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 235 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

02 फरवरी, 2015

संख्या-4/नि0सं0-12-54/2014 का.- 2012 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री अखिलेश कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं, देवघर को (क) दिनांक 15 अप्रैल, 2013 से 29 अप्रैल, 2013 तक पितृत्व अवकाश के रूप में वित्त विभागीय संकल्प सं0-551, दिनांक 01 मार्च, 2007 एवं संकल्प

संकल्प संख्या-997 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के आलोक में तथा (ख) दिनांक 30 अप्रैल, 2013 से 13 मई, 2013 तक उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

12 मार्च, 2015

संख्या- 3/पद-01(घ)-06/2014 का.- 2370-- वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची से सेवा प्राप्त श्री डी०के० तेवतिया, भा०व०से० (झा: 88) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री तेवतिया अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, जेडा, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार बाजपेयी,

सरकार के अवर सचिव।

शुद्धि पत्र

14 मार्च, 2015

संख्या-4/नि० सं०-12-112/2014 का. 2402-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-2011, दिनांक 02 फरवरी 2015 (छायाप्रति संलग्न) में

अंकित तिथि "दिनांक 02 फरवरी 2015" के स्थान पर "दिनांक 02 मार्च 2015" पढ़ा जाय ।

उक्त निर्गत अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत् रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा काँशी,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

शुद्धि पत्र

14 मार्च, 2015

संख्या-4/नि0 सं0-12-54/2014 का. 2403-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-2012, दिनांक 02 फरवरी 2015 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित तिथि "दिनांक 02 फरवरी 2015" के स्थान पर "दिनांक 02 मार्च 2015" पढ़ा जाय।

उक्त निर्गत अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत् रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा काँशी,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

नगर विकास विभाग

संकल्प

13 मार्च 2015

विषय:-जलापूर्ति योजना में House to House Connection, जल संयोजन शुल्क के संबंध में ।

संख्या-5/नवि0/जला-01/2015/904-- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम] 1993 एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार शहरी निकाय के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना शहरी स्थानीय निकाय का दायित्व है ।

2. पूर्व में राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत जलापूर्ति योजनाओं के प्राक्कलन में गृह जल संयोजन (House to House Connection) की राशि का प्रावधान नहीं किया जाता था, बल्कि सभी शहरी नागरिकों को जल संयोजन शुल्क जमा करने के पश्चात् जल संयोजन (Water Connection) लेने की व्यवस्था थी ।

3. जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान मिशन (JnNURM) अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्राक्कलन में House to House Connection की राशि का प्रावधान किया जाता रहा है। JnNURM की भाँति राज्य योजनान्तर्गत संचालित जलापूर्ति योजनाओं में House to House Connection का समावेश किये जाने एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी नागरिकों को जल संयोजन शुल्क माफ करने का मामला सरकार के विचाराधीन था ।

4. सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि,

(i) गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार (House hold) (APL) को जल संयोजन शुल्क के रूप में - 4,000 रुपये - (One time) Charge के रूप में जमा करना होगा। APL से वसूली गई राशि राज्य सरकार के राजस्व में जमा किया जायेगा ।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (House hold) (BPL) के लिए जल संयोजन निःशुल्क होगा ।

(iii) APL/ BPL द्वारा जलदर जमा करना होगा जो त्रैमासिक होगा तथा इस राशि को संबंधित नगर निकाय अपने म्युनिशिपल एकाउंट में जमा करेंगे जिसे वे जलापूर्ति योजना के रख-रखाव (O&M) पर व्यय करेंगे ।

गरीब परिवारों को भी जल संयोजन हेतु निकाय द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तथा निकाय द्वारा निर्धारित जलदर का भुगतान करना पड़ेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।
